उत्तरोत्तरयुक्तिपूर्ण बनाया गया है। इसके अलावा, आयकर अधिनियम, 1961 में अनेक ऐसे उपबंध हैं, जिनका उद्देश्य काले धन के पैदा होने को रोकना है। इसके अन्तर्गत अन्य के साथ-साथ धारा 44-क क और 44-क ख के अन्तर्गत उचित मामलों में लेखों को अनिवार्य रूप से रखना और उनकी लेखा-परीक्षा, धारा 40-क(3), 269 ध ध और 269-न के अन्तर्गत नकद लेन-देनों पर प्रतिबंध, अध्याय ग के अन्तर्गत सम्पत्तियों की पूर्व क्रयाधिकार खरीद से संबंधित उपबंध और कर चूककर्ताओं को दंड देने के लिए अर्थदंडों और अभियोजनों से संबंधित उपबंध शामिल हैं। इस अधिनियम में कर अपवचन का पता लगाने के लिए सम्मनों, सर्वेक्षणों और तलाशियों आदि से संबंधित उपबंध भी निहित है। उचित मामलों में इन उपबंधों का सहारा लिया जाता है। प्रतिवर्ष बढ़ता हुआ कर राजस्व इन उपायों की सफलता का संकेत देता है।

रुपए के मूल्य में गिरावट आना

61. **श्री जनेश्वर मिश्र:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विदेशी मुद्रा बाजार में अमरीकी डालर के मुकाबले भारतीय रुपए में निरन्तर आ रही गिरावट के संबंध में सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं;

(ख) सरकार भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले इसके प्रभाव को किस तरह से दूर करने का विचार रखती है;

(ग) डालर के मुकाबले अन्य विकसित देशों की मुद्राओं एवं भारतीय रुपए में गिरावट का प्रतिशत क्या है;

(घ) क्या यह सच है कि मुद्रास्फीति बढ़ने से रुपए के मूलय में गिरावट हो रही है; और

(ङ) इस संबंध में तथ्य संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देबी प्रसाद पाल): (क) हाल की अवधि में अवलोकित रुपए की विनिमय दर में अत्यधिक अस्थिरता अव्यवहारिक कारणों से थी। भारतीय रिजर्व बैंक ने सट्टेबाज तत्वों की समाप्ति के लिए विदेशी मुद्रा बाजार के हाजिर और वायदा दोनों खण्डों में हस्तक्षेप किया। इसके अतिरिक्त, भारतीय रिजर्व बैंक ने सट्टेबाजी का सामना करने के लिए 7.2.1996 को कुछ मजबूत उपायों की भी घोषणा की। इनमें ये शामिल हैं:— (1) अमरीकी डालर में मूल्यवर्गित लदान-पश्च नियति ऋण संबंधी योजना का समापन (2) 90 दिन से ऊपर के लिए लदान-पांच नियति रुपया ऋण पर ब्याज दर को मुक्त करना, (3) आयात वित्त पर ब्याज प्रभार में 15 प्रतिशत से 25 प्रतिशत तक की वृद्धि करना, और (4) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वायदा संविदाओं को निरस्त करने और प्राधिकृत डीलरों के अंतः दिवसीय सौदों की मानीटरिंग। ये उपाय 8.2.1996 के प्रभावी हुए। इन उपायों की घोषणा के बाद से विदेशी मुद्रा बाजार में स्थिरता आई है। रुपया-डालर दर में सुधार हो कर 23.2.1996 को यह 36.56 रुपए प्रति अमरीकी डालर हो गयी है। विनिमय दर गतिविधियों की सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक दोनों के द्वारा लगातार मानीटरिंग की जा रही है और जब कभी आवश्यक होगा मुद्रा दर में अत्यधिक अस्थिरता का सामना करने और सुव्यवस्थित बाजार स्थितियों को बनाए रखने के लिए अतिरिक्त उपाय किए जाएंगे।

(ख) हाल के महीनों में रुपए की विनिमय दर में समस्त उतार-चढ़ाव सुदृढ़ प्रतिस्पर्द्धा पर आधारित व्यवहार्य भुगतान संतुलन के दीर्घावधिक उद्देश्यों के समनुरूप है।

(ग) 31 मार्च, 1995 को प्रभावी दरों की तुलना में 16 फरवरी, 1996 को अमरीकी डालर की तुलना में रुपए और प्रमुख मुद्राओं के अवमूल्यन का विवरण नीचे दिया गया है:—

मुद्रा	अवमूल्यन (-) अमरीकी डालर की तुलना में (प्रतिशत)
भारतीय रुपया	- 14.1
जापानी येन	- 17.7
पौंड स्टर्लिंग	- 4.3
ड्यूश मार्क	- 5.6
फ्रांसीसी फ्रांक	- 3.9

(घ) और (ङ) मार्च 1993 और जुलाई 1995 के बीच दो वर्षों की अवधि में अमरीकी डालर की तुलना में रुपए की विनिमय दर स्थिर बनी रहीं। इस अवधि के दौरान भारत में मुद्रास्फीति की दर भारत के प्रमुख व्यापार भागीदार देशों में मुद्रास्फीति की दरों की तुलना में उच्च थी। भारत और विदेशों के बीच मुद्रास्फीति में इन अंतरों का तात्पर्य रुपए के विदेशी मूल्य में वास्तविक अधिमूल्यन और भारत की प्रतियोगितात्मकता में क्षरण

होना था। हाल के महीनों में रुपए की विनिमय दर में अवमूल्यन ने 1993-94 से आरम्भ हुए वास्तविक अधिमूल्यन को सही किया है। भारत में मुद्रास्फीति की दर में हाल ही में महत्वपूर्ण रूप से गिरावट आकर यह 4.5 प्रतिशत से कम रह गई है।

Package on Rupee Slide

62. SHRI O.P. KOHLI: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether the Reserve Bank of India is under pressure from the Commerce Ministry and the leading Chambers of the country to alter its latest package on rupee slide to take care of the demands of the exporters;

(b) if so, the details thereof;

(c) the reaction of Government thereto;

(d) whether there is any proposal to alter the package and if so, the reasons therefor;

(e) whether the exporters have adopted unfair means to loot the exchaquer and is there any proposal to tighten the law on them; and

(f) the details of cases of irregularities pending in the Banks in the matter of foreign exchange, bank-wise?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (DR. DEBIPROSAD PAL): (a) to (d) The Ministry of Commerce has been receiving representations from individual exporters as well as export and trade associations expressing concern over the latest package of measures announced by the RBI on 7.2.1996. The RBI monitors developments in the foreign exchange market closely and continuously and, in consultation with the Government, undertakes measures to correct market behaviour which is out of alignment with fundamentals. The measures undertaken by the RBI recently are addressed at the lags and leads in receipts and payments which have adversely affected market flows. These measures are intended to accelerate net receipt of foreign exchange and are expected to bring about stability in the foreign exchange market. The RBI would continue to minitor the foreign exchange market and undertake policy measures and/or changes in the existing measures to counter excessive volatility in the exchange rate and to maintain orderly market conditions.

(e) In the recent period, it has been observed that there has been a tendency on the part of exporters to delay realisation of export proceeds. In terms of Rule 8 of the Foreign Exchange Regulation Rules, 1974, the amount representing the full export value of the goods exported shall be realised and be paid by the exporters to the authorised dealer on the due date for payment or within six months from the date of shipment of the goods, whichever is earlier. Failure to comply with this statutory obligation would invite punitive action under the Foreign Exchange Regulation Act. The Reserve Bank of India has also decided to monitor cancellation of forward contracts booked by authorised dealers for amounts of US $100,000 and above. Such cancellations are required to be reported to the Reserve Bank of India on a weekly basis. The Reserve Bank has also decided to monitor the US Dollar/India rupee intra-day trading transactions of authorised dealers.

(f) The requisite information is being collected and will be placed on the Table of the House as early as possible.

हरियाणा में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का खोला जाना

63. श्री रामजीलाल: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गांवों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खोले जाने सम्बन्धी मानदण्ड क्या हैं और उनके दायित्व क्या है;